

मेन्स मास्टर

अरबपति राज का उदय

भारत में आय और धन असमानता, 1922-2023: अरबपति राज का उदय
नितिन कुमार भारती, लुकास चांसल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमांची की एक रिपोर्ट

प्रसंग

- 1922 से 2023 तक भारत में आय और धन असमानता के दीर्घकालिक विकास की जांच करता है
- राष्ट्रीय खातों, कर डेटा, सर्वेक्षण, समृद्ध सूचियों से डेटा को संयोजित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है
- भारत की बड़ी आबादी और वैश्विक असमानता पर प्रभाव को देखते हुए असमानता का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है

असमानता के स्तर पर निष्कर्ष

आय असमानता

- समाजवादी नीतियों के बीच शीर्ष 1% की आय हिस्सेदारी औपनिवेशिक युग में 20% से घटकर 1982 तक 6.1% हो गई
- लेकिन तब से तेजी से वृद्धि हुई, 2022-23 में 22.6% तक पहुंच गई, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है
- शीर्ष 0.1% की हिस्सेदारी लगभग 10%, शीर्ष 0.001% (लगभग 9,000 व्यक्ति) ने कुल आय का 2% से अधिक अर्जित किया
- इसके विपरीत, निचले 50% की हिस्सेदारी 1982 में 23.6% से आधी से भी अधिक घटकर 2022-23 में केवल 15% रह गई है।
- विकास घटना वक्र दिखाते हैं कि 1980 के दशक के बाद आय वृद्धि शीर्ष 10%, विशेष रूप से शीर्ष 1% की ओर अत्यधिक झुक गई है

धन संबंधी समानताएं

- शीर्ष 1% की संपत्ति हिस्सेदारी 1961 में 13% से लगभग तीन गुना होकर 2022-23 में 40.1% हो गई
- शीर्ष 0.1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 30% है
- कुल संपत्ति का 16% से अधिक केवल लगभग 10,000 व्यक्तियों के पास है (शीर्ष 0.001%)
- शीर्ष शेरों में वृद्धि के कारण निचले 50% और मध्य 40% के धन शेरों में गिरावट आई

धन-आय अनुपात

- 2022 में धन वितरण के निचले स्तर के लिए केवल 30-40% से बढ़कर शीर्ष 0.001% के लिए 4600% से अधिक की तीव्र वृद्धि
- पारंपरिक दृष्टिकोण के विपरीत, शुद्ध संपत्ति के मामले में भारत की कर प्रणाली विरोधाभासी रूप से प्रतिगामी है
- भारतीय राजनेताओं के धन के खुलासे का अध्ययन करने वाले हालिया कार्य के अनुरूप गंभीर निहितार्थ
- इस तरह की अत्यधिक एकाग्रता अभिजात वर्ग को समाज, सरकार पर असंगत प्रभाव डालने की अनुमति देती है
- लोकतंत्र को कमजोर करने वाले धनिकतंत्र के खतरे के बारे में गंभीर चिंताएं उठाता है
- मुख्य बातें भारत की विकास प्रक्रिया लाभ वितरण में काफी असमान रही है

एमपीआई में कमी = असमानता में कमी

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई), जो जनसंख्या को न्यूनतम सीमा से नीचे मापता है, में गिरावट का मतलब जरूरी नहीं कि असमानता में कमी हो
- ऐसा इसलिए है क्योंकि गिनी गुणांक जैसे असमानता के उपाय संपूर्ण वितरण को देखते हैं
- भारत की अच्छी आर्थिक वृद्धि ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला
- लेकिन विकास प्रक्रिया की प्रकृति विषम हो गई, जिससे वितरण के शीर्ष को असमान रूप से लाभ हुआ
- गरीबी कम करने में सहायता करते समय, सरकारी हस्तंतरण ने शीर्ष पर केंद्रित बाजार आय से असमानता को कम करने में बहुत कम योगदान दिया
- इसके अलावा, गरीबी से बाहर निकलने वालों के बीच उत्पादक संपत्ति के स्वामित्व की कमी उनकी धन संचय करने की क्षमता और ऊपर की ओर गतिशीलता को सीमित करती है

नीति क्रियान्वयन

- रिपोर्ट में भारत के अति-अमीरों को ध्यान में रखकर एक व्यापक संपत्ति कर लागू करने की मांग की गई है
- आय के अतिरिक्त धन का स्पष्ट हिस्सा लगाने के लिए कर संहिता के पुनर्गठन की वकालत
- स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण में समावेशी सार्वजनिक निवेश को सक्षम करने के लिए राजकोषीय संसाधन उत्पन्न करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया
- आर्थिक लाभ को अधिक व्यापक आधार पर साझा करने की सुविधा के लिए ऐसे उपाय महत्वपूर्ण हैं

डेटा चुनौतियाँ और पारदर्शिता की आवश्यकता

- अंतर्राष्ट्रीय डेटा स्रोतों की गुणवत्ता, कवरेज और पारदर्शिता को लेकर गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं
- 2011-12 के बाद से कोई भी राष्ट्रव्यापी उपभोग सर्वेक्षण डेटा निचले वितरण के आसपास अनिश्चितता पैदा नहीं करता है
- 1999-2010 और 2018-2021 में कर डेटा जारी करने में अनियमित अंतराल शीर्ष शेरों के अनुमान में बाधा डालता है
- कुल आय नियंत्रण के रूप में उपयोग किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद डेटा के संभावित अति-आकलन को लेकर बढ़ती चिंताएं
- साक्ष्य-आधारित नीतियों को सक्षम करने के लिए सरकार द्वारा अधिक डेटा लोकतंत्रीकरण और पारदर्शिता का आह्वान

निष्कर्ष

रिपोर्ट भारत के "अरबपति राज" अभिजात वर्ग में असाधारण रूप से उच्च स्तर की आय और धन एकाग्रता को चित्रित करती है। जबकि आर्थिक विकास ने गरीबी को कम करने में मदद की है, यह लाभ का अधिक न्यायसंगत वितरण उत्पन्न करने में विफल रहा है, धन और आय शीर्ष पर जबरदस्त रूप से केंद्रित रहे हैं। इसे संबोधित करने के लिए ठोस नीतिगत कार्यवाई की आवश्यकता है, लेकिन डेटा गुणवत्ता और पहुंच संबंधी चुनौतियों के कारण इसमें बाधा बनी हुई है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

रेलवे का समर्पित माल गलियारा पूरा होने के करीब, महत्वाकांक्षा बड़ी

1. परिचय

- भारतीय रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना पूरी होने के करीब है
- भारत के लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण मील का पथर
- लेख पृष्ठभूमि, उद्देश्यों, प्रभाव, चुनौतियों और भविष्य की कार्यवाई की पड़ताल करता है

2. पृष्ठभूमि

- माल परिवहन के लिए एक समर्पित उच्च गति, उच्च क्षमता वाले रेलवे कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव 18 साल पहले रखा गया था
- दो मुख्य गलियारों:**
 - वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)
 - जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (मुंबई) से दादरी (उत्तर प्रदेश) तक 1,506 किमी
 - दिसंबर 2020 से परिचालन
 - पूर्वी समर्पित माल गलियारा (ईडीएफसी)
 - लुधियाना से दानकुनी (पश्चिम बंगाल) तक 1,337 किमी
 - अप्रैल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद

3. समर्पित माल गलियारा: एक सिंहावलोकन

- माल परिवहन में क्रांति लाने के लिए भारतीय रेलवे का विशेष प्रयोजन वाहन
- उद्देश्य:
 - मौजूदा रेल नेटवर्क को कम करना
 - समय की पाबंदी बढ़ाएँ
 - परिवहन लागत कम करें
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित:
 - उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम
 - आधुनिक लोकोमोटिव
 - उच्च क्षमता वाले वैगन

4. अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव

- भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव
- फायदे:
 - रसद लागत में कमी
 - ट्रेन की गति में वृद्धि (20-25 किमी प्रति घंटे से 60-75 किमी प्रति घंटे)
 - कॉरिडोर 65-100% क्षमता पर चल रहा है
- विभिन्न उद्योगों के लिए लाभ:
 - विनिर्माण
 - कृषि
 - ई-कॉमर्स
- डीएफसी में खेप स्थानांतरित करने वाली कंपनियाँ (उदाहरण के लिए, विसम एक्सप्रेस, अमेजॉन)
 - डीएफसी नेटवर्क का उपयोग करने के लिए ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनियों से बातचीत
 - ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए विशेष कोच पेश किए जा रहे हैं
 - वैश्विक बाजार में भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना

5. चुनौतियाँ और सीखे गए सबक

- कार्यान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियाँ:
 - पूरा होने में देरी (प्रस्ताव के 18 साल बाद)
 - पर्याप्त लागत (₹1.24 लाख करोड़)

- भूमि अधिग्रहण
 - पर्यावरणीय मंजूरी
 - अनेक हितधारकों के साथ समन्वय
 - सफल समापन भारतीय रेलवे के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है
 - सीखें गए सबक भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अमूल्य हैं
- 6. भविष्य का रोडमैप**
- अगले 30 वर्षों में 457 मिलियन टन माल परिवहन का लक्ष्य
 - बुनियादी ढांचे और रोलिंग स्टॉक का निरंतर उन्नयन:
 - पुराने कोचों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करना
 - आधुनिक, उच्च क्षमता वाले यंत्रों के साथ प्रतिस्थापन
 - निर्बाध मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स के लिए अन्य परिवहन साधनों (बंदरगाहों, राजमार्गों) के साथ एकीकरण
 - समर्पित माल गलियारों के और विस्तार का मार्ग प्रशस्त करना
 - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना और आर्थिक विकास को समर्थन देना
- 7. निष्कर्ष**
- डीएफसी: भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक गेम-चेंजर
 - अत्यधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की संभावना
 - चुनौतियों के बावजूद सफल समापन
 - बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है
 - देश में माल परिवहन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका
 - अधिक लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए मंच तैयार करना

भारत का हेपेटाइटिस सिरदर्द

- भारत का हेपेटाइटिस सिरदर्द**
- वैश्विक बोझ:**
- वायरल हेपेटाइटिस विश्व स्तर पर तपेदिक जितनी ही लोगों की जान लेता है
 - वैश्विक हेपेटाइटिस का भार 10 देशों पर पड़ता है, जिसमें भारत भी शामिल है
- सबसे अधिक हेपेटाइटिस के बोझ वाले शीर्ष 10 देश:**
- चीन: 83.8 मिलियन मामले
 - भारत: 28 मिलियन मामले (तीसरा उच्चतम)
 - नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया भी शीर्ष रैंक में
- हेपेटाइटिस को समझना:**
- वायरस से होने वाले 5 प्रकार (ए, बी, सी, डी, ई)
 - दूषित भोजन, पानी, रक्त के माध्यम से फैलता है
 - लक्षण: बुखार, पीलीपा, पेट दर्द
 - कुछ क्रोनिक लीवर रोग और कैंसर का कारण बनते हैं
- भारत की स्थिति:**
- राष्ट्रीय कार्यक्रम के बावजूद अल्प निदान एवं अनुपचारित
 - 10 में से केवल 1 मामले में ही बी बी का निदान किया जाता
 - उपचार में कई पात्र मरीज शामिल नहीं हैं
- प्रमुख चुनौतियाँ:**
- कम टीकाकरण दर, विशेष रूप से हेप बी के लिए
 - व्यापक जांच और निदान का अभाव
 - सीमित उपचार पहुंच और कवरेज
 - कुछ प्रकारों के लिए अल्प उपचार अवधि
- अंतर पाठना:**
- जागरूकता बढ़ाएं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करें
 - डेटा संग्रह और निगरानी में सुधार करें
 - टीकाकरण, जांच और उपचार की पहुंच बढ़ाएं
 - बेहतर नैदानिक परीक्षणों और नई दवाओं में निवेश करें
- आगे का रास्ता:**
- हेप बी के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण
 - सभी प्रकार के लिए व्यापक स्त्रीनि
 - किफायती परीक्षण और उपचार सुनिश्चित करें
 - कलंक और प्राथमिकता की कमी को संबोधित करें

प्रिलिम्स बूस्टर

ब्रह्माण्ड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है? नया डेटा रहस्य खुला रखता है

- ब्रह्माण्ड का विस्तार: एक ब्रह्मांडीय रहस्य**
- पृष्ठभूमि और संदर्भ:**
- बिग बैंग सिद्धांत लगभग 13.8 अब्ज साल पहले अविश्वसनीय रूप से गर्म, घने राज्य से तेजी से विस्तार करने वाले ब्रह्माण्ड का वर्णन करता है
 - एक बुनियादी सवाल: वर्तमान में ब्रह्माण्ड कितनी तेजी से फैल रहा है?
- मुख्य परिभाषाएँ:**
- हबल स्थिरांक: ब्रह्माण्ड की विस्तार दर को बताने वाली इकाई
 - लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल: आकाशगंगा वितरण जैसे अवलोकनों को समझाने वाला सबसे सरल मॉडल
 - सेफिड वैरिएबल्स: स्पष्टित तारे का उपयोग ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है
- तनाव:**
- दो वैध लेकिन परस्पर विरोधी विधियाँ अलग-अलग हबल स्थिरांक मानों का अनुमान लगाती हैं
 - सेफिड वैरिएबल्स का उपयोग करते हुए कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर
 - लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल ब्रह्मांडीय विशेषताओं का विश्लेषण करता है

- निष्कर्ष:**
- हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि विसंगति सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, डेटा त्रुटियों के कारण नहीं
 - भौतिकी ड्राइविंग विस्तार की अदृश्य समझ का सुझाव देता है
- ! रहस्य बना हुआ है:**
- क्या ब्रह्माण्ड की विस्तार दर स्थिर है, बढ़ रही है, या धीमी हो रही है?
 - वर्तमान ब्रह्माण्ड संबंधी मॉडलों से परे नई भौतिकी की संभावित आवश्यकता?
 - चल रहे अवलोकनों का उद्देश्य तनाव को हल करना और विस्तार दर को परिष्कृत करना है
- महत्व:**
- हबल स्थिरांक तनाव का समाधान निम्न के लिए महत्वपूर्ण है:
 - हमारे ब्रह्माण्ड के विकास और भाग्य को समझें
 - हमारे ब्रह्माण्ड संबंधी सिद्धांतों की सीमाओं का परीक्षण करें
 - संभावित रूप से सबसे बड़े पैमाने पर नई भौतिकी की खोज करें

क्रायोजेनिक्स: इसे ठंडा रखें

- क्रायोजेनिक्स: अत्यधिक ठंड पर काबू पाना**
- परिभाषा और मूल बातें:**
- क्रायोजेनिक्स -153°C (-243°F) से नीचे, बेहद कम तापमान पर सामग्रियों का अध्ययन और अनुप्रयोग है।
 - इन अति-निम्न तापमान पर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और वायु जैसी गैसों भी द्रव में संचित हो जाती हैं
 - क्रायोजेनिक तरल पदार्थ जैसे तरल हीलियम (-269°C) और तरल नाइट्रोजन (-196°C) का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है
- क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज:**
- क्रायोजेनिक तरल पदार्थों को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और स्थानांतरित करने के लिए वैक्यूम फ्लास्क और इंसुलेटेड पाइपलाइन जैसे विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है
 - क्रायोजेनिक तापमान को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन्नत प्रशीतन और शीतलन प्रणाली की आवश्यकता होती है
 - सामग्री क्रायोजेनिक तापमान पर बहुत अलग ढंग से व्यवहार करती है, अद्वितीय गुण और चरण परिवर्तन प्रदर्शित करती है
- मुख्य अनुप्रयोग:**
- रॉकेट प्रणालय:** तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शक्तिशाली क्रायोजेनिक रॉकेट ईंधन हैं (जैसे, इसरो के क्रायोजेनिक इंजन)
 - सामग्री विज्ञान:** क्रायोजेनिक उपचार से स्टील जैसी धातुओं की ताकत और स्थायित्व में काफी सुधार हो सकता है
 - मेडिकल इमेजिंग:** एमआरआई मशीनों में बेहतर छवि गुणवत्ता के लिए सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा करने के लिए तरल हीलियम का उपयोग करती हैं
 - ऊर्जा भंडारण:** हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस जैसी तरलकृत गैसों उच्च-घनत्व, कुशल ऊर्जा भंडारण को संक्षम बनाती हैं

भारत की वीवीपीटी प्रणाली को समझना

- वीवीपीटी क्या है?**
- वीवीपीटी = वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट प्रणाली
 - ईवीएम वोटों की गिनती का ऑडिट करने और संभावित त्रुटियों का पता लगाने की एक विधि
 - ईवीएम पर डाले गए प्रत्येक वोट के लिए एक पेपर डील प्रदान करता है
- वीवीपीटी कैसे काम करता है:**
- मतदाता ईवीएम पर वोट डालता है
 - ईवीएम से जुड़ा वीवीपीटी प्रिंटर वोट विवरण के साथ पेपर स्लिप उत्पन्न करता है
 - मतदाता एक दृश्य विंडो के माध्यम से पेपर स्लिप पर अपना वोट सत्यापित कर सकता है
 - संभावित ऑडिट के लिए पेपर पर्चियों को सुरक्षित वीवीपीटी ड्राइव बॉक्स में संग्रहित किया जाता है
- वीवीपीटी ऑडिट प्रक्रिया:**
- चुनाव आयोग एक सांख्यिकीय नमूनाकरण पद्धति का पालन करता है
 - प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपीटी ऑडिट के लिए यादृच्छिक ईवीएम का चयन किया गया
 - वीवीपीटी पेपर पर्चियों की गिनती की गई और उनका मिलान ईवीएम वोटों से किया गया
 - ईवीएम परिणामों की अखंडता को माप्य करने में मदद करता है
- प्रमुख लाभ:**
- ईवीएम मतदान की पारदर्शिता और सत्यापनीयता बढ़ जाती है
 - ईवीएम वोटों की गिनती का क्रॉस-सत्यापन संक्षम बनाता है
 - चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ता है
 - संभावित विवादों या आरोपों को सुलझाने में मदद करता है